

Shri Mehr Chand Khanna: What the State Governments have done is this. They have cut down their own allocations and diverted the money meant for housing to other projects, and they are asking the Centre to find more funds, and the Finance Minister very rightly told them that if they made an effort he was prepared to help them, but that he could not fill up the gap.

Shri Shivananjappa: May I know whether there is a cut in the allocation meant for rural housing also?

Shri Mehr Chand Khanna: It is an all-round cut, and it will affect rural housing also.

Shri P. R. Patel: May I know whether any allocations is made to subsidise houses for the agricultural labourers and agriculturists?

Shri Mehr Chand Khanna: I do not think I deal with them. That is the concern of the Ministry of Food and Agriculture.

Dr. Sarojini Mahishi: What is the percentage of reduction in housing in the various States, and which section of the housing scheme is being affected, specially?

Shri Mehr Chand Khanna: The reduction is to the extent of 50 per cent. There has been a certain amount of misunderstanding, which was clarified by the Planning Minister only two days ago, namely that the directive issued by the NDC and the Planning Commission has been interpreted very literally. The idea is that as far as industrial housing is concerned, it should be given a very high priority. Unless we can put up houses for industrial workers, it will not help the production programme in the country.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that the State Governments have been asked by the Centre to raise additional resources for these housing schemes, and if so have they expressed their inability to do so?

Shri Mehr Chand Khanna: No. What the State Governments have

been asked is this, that the money meant for housing under the Plan should not be diverted to other projects.

Shri P. Kunhan: Is it a fact that the progress of plantation labour housing schemes is very poor, and if so, what steps have been taken for implementing it?

Shri Mehr Chand Khanna: That is so. The difficulty has been about the element of subsidy. To industrial workers we are giving a certain amount of subsidy, about 25 per cent. Now, what has been suggested is that the same subsidy should be given in the matter of plantation labour. The Planning Minister is setting up a small working group to examine this matter.

गंडक नारायणी बाढ़ नियंत्रण योजना

+

*६२३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत मा आजाद ;

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, नेपाल सरकार ने गंडक नारायणी बाढ़ नियंत्रण योजना के अघीन बांध बनाने की स्वीकृति दे दी है, और

(ख) इस योजना के सम्बन्ध में नवीनतम प्रगति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० ए० मेहदी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभापटल पर रखा है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०— ११६२।६३]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि नेपाल सरकार ने आखिर इस बांध को बनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि देर से यह अनुमति मिलने के कारण इस काम में बहुत बाधा पड़ी है और हार्न हुई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि देरी से स्वीकृति मिलने के कारण क्या थे ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): It is not right to say that the Nepal Government has been delaying matters. Their engineers and our engineers have been discussing this question. The Gandak Board has decided to make this an integral part of the project, and as soon as the joint inspection that was decided upon by the Government of Nepal was held, they have given the green signal and asked us to take over the lands after depositing the money that is required. The UP Government is seized of the matter, and I hope the construction will start soon.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध का निर्माण देर से देर कब तक शुरू हो जायगा और कब तक समाप्त हो जायगा और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दे रही है ?

Shri Alagesan: I had a talk with the Minister for Irrigation in this regard. They are very anxious to take up this work as early as possible. The only question that will have to be considered is that any work that may be undertaken now should not become infructuous after the monsoons set in. Subject to that, they will proceed with this work as quickly as possible.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में अपनी ओर से क्या सहायता दे रही है ?

Shri Alagesan: The Central Government will not give any aid.

Dr. K. L. Rao: May I know whether hydraulic model studies have been made or are proposed to be made to study the effect of the embankments on the left bank of the river?

Shri Alagesan: All these studies have been gone through and the alignment has been settled. It think only

the work of construction remains to be undertaken.

Dr. K. L. Rao: I refer to model studies of the effect of the right side embankments on the left bank of the river. Have they been made?

Shri Alagesan: As far as my information goes all these studies that are necessary, that should precede such a work have been made, and if anything remains to be done, it would be undertaken.

श्री क० ना० तिवारी : इस बारे में नेपाल गवर्नमेंट को राजी करने के लिए उस को क्या-क्या सुविधाएँ दी गई हैं ?

श्री सं० अ० मेहदी : नेपाल गवर्नमेंट को सुविधा देने के लिए उनके इंजीनियर्स वगैरह ने उस जगह का मुआयना किया और यू० पी० सरकार के गंडक कंट्रोल बोर्ड के लोगों ने वहाँ पर जाकर उनसे बात करके थह मामला तय किया है।

Mr. Speaker: Whether any facilities have been given to Nepal Government in order to get that Government's consent—that is the question.

श्री सं० अ० मेहदी : जहाँ तक कन्सेशन का ताल्लुक है, उनको एक बांध दिया गया है, जिसकी वजह से नेपाल का बहुत सा हिस्सा फलडूज से बचेगा और उसमें खेती वगैरह हो सकेगी और पावर हाउस से पूरी पावर भी उसको दी जायगी।

Shri K. C. Pant: What is the total cost of this project and will Nepal contribute any share of it?

Shri Alagesan: The project will be entirely financed by us. I am not able to say the total cost.

Shri Sham Lal Saraf: When this project is completed, will it be a multi-purpose project? Besides flood protection, what will be the power potential?

Shri Alagesan: There will be a flood embankment and also a canal.

It will mean irrigation also. So that it is both for irrigation and flood control.

चांदी का भाव

+

*१२४. { श्री श्रीकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू होने के बाद चांदी का भाव काफी कम होने की बजाय बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भाव में इस वृद्धि को रोकने के लिये कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) चांदी की मौसमी मांग के कारण और इसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने से लगभग जनवरी १९६३ के मध्य से चांदी के भाव बढ़ गये हैं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार के किसी भी प्रस्ताव को पहले से बताना सम्भव नहीं है।

[(a) There has been an increase in prices of silver since about the middle of January 1963 on account of the seasonal demand for the metal and in sympathy with the rise in international prices of silver.

(b) and (c) It is not possible to indicate in advance any proposals which Government may have in this regard.]

श्री श्रीकारलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या चांदी की कीमतों के उतार-चढ़ाव का कोई असर मुद्रा-स्फीति

पर भी पड़ता है, अगर हां, तो किस हद तक।

श्री ब० रा० भगत : कोई सीधा असर नहीं पड़ता है।

श्री श्रीकारलाल बेरवा : क्या दुकानों पर इसकी भी मूल्य-सूची टांगने के बारे में सरकार का कोई विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : चांदी के भाव तो रोज-रोज मार्केट में निकलते हैं जो कि रोज अखबारों में छपते हैं। इसलिए अलग-अलग दुकानदारों के मूल्य-सूची रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री बड़े : मंत्री महोदय ने कहा है कि गोल्ड कंट्रोल आर्डर से चांदी की कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन क्या गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिज में कोई इन्टर-कनेक्शन है या नहीं और प्राइसिज पर इसका भी असर हुआ है या नहीं ? अगर हुआ है, तो क्या चांदी की एडवांस स्पेकुलेशन को बन्द करने का सरकार का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : थोड़ा बहुत असर हुआ हो। लेकिन जो बड़े असर हैं, वे मैंने बताये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव बढ़ने लगा है। १९६२ में भाव गिर गया था और १९६३ में वह बढ़ गया। इसका असर यहां भी पड़ा। सीजनल डिमांड होती है, जैसे आजकल शादियों और दूसरी वजह से डिमांड बढ़ गई है। गोल्ड कंट्रोल होने की वजह से यह हो सकता है कि थोड़ी बहुत चांदी की मांग बढ़ गई हो, थोड़ी बहुत उसका असर पड़ा हो लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं हुआ है।

श्री बड़े : बन्द करना चाहते हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह चीज आपको क्यों बतायेंगे अइस वक्त।